हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 121 लखनऊ शुक्रवार 19 दिसम्बर 2025 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और सर्वोच्च सम्मान

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए मिला ऑर्डर ऑफ ओमान

एजेंसी

मस्कट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओमान ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। राजधानी मस्कट में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। ओमान समेत तीन देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पीएम मोदी अभी ओमान के दौरे पर है, जो उनके तीन देशों के दौरे का अंतिम पड़ाव है, वे आज ही ओमान से वापस स्वदेश लौटेंगे। वे 15 से 18 दिसंबर के बीच जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर गए थे। इथियोपिया ने भी पीएम मोदी को किया सम्मानित इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया ने भी ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया था। यह सम्मान इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली ने उन्हें दिया था। बता दें कि पीएम मोदी इस सम्मान को पाने वाले दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए मिला चौंपियन ऑफ द अर्थ सम्मान पीएम मोदी को संयुक्त राष्ट्र ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए श्चौंपियन ऑफ द अर्थश पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और प्रभाव का परिचायक हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना को अपनाते हुए वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत किया है। उनकी विदेश यात्राएं नए व्यापारिक अवसर, निवेश और सांस्कृतिक आदान–प्रदान का माध्यम बनी हैं।

अगले साल डेढ़ लाख नौकरियां देगी सरकार, सीएम ने उच्चाधिकारियों से विभागवार खाली पदों का मांगा ब्योरा

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश सरकार अगले साल डेढ़ लाख नौकरियां देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों से विभागवार सरकारी नौकरी के खाली पदों का ब्योरा मांगा था, जिसके बाद डेढ़ लाख रिक्त पदों पर भर्ती करने की अनुमति दी है। युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर पुलिस, शिक्षा, राजस्व, आवास विकास समेत विभिन्न विभागों में दी जाएगी। सबसे अधिक पुलिस और शिक्षा विभाग में भर्तियां होंगी। इसके साथ 2026 में यूपी सरकार के नाम सबसे अधिक सरकारी नौकरी देने का रिकार्ड भी दर्ज हो जाएगा। बता दें कि प्रदेश सरकार ने बीते साढ़े आठ वर्ष के दौरान विभिन्न विभागों में साढ़े आठ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। सूत्रों की मानें तो वर्ष 2026 में पुलिस और शिक्षा विभाग में करीब 50–50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। वहीं राजस्व विभाग में लेखपाल समेत 20 हजार पदों पर भर्ती होगी। इसी तरह कारागार, आवास विकास, बाल विकास पुष्टाहार, स्वास्थ्य विभाग में भी रिक्त पदों को भरा जाएगा। विभागों में भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी करने की कवायद जारी है। प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में अब तक 2.19 लाख पदों पर भर्ती कर चुकी है। वर्ष 2026 में पुलिस में 30 हजार सिपाही, 5 हजार सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा विभाग में 15 हजार विभिन्न पदों पर भी भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक से लेकर लेक्चरर, प्रधानाचार्य आदि के 50 हजार पदों पर भर्ती होगी। स्वास्थ्य, आवास विकास, कारागार, बाल विकास पुष्टाहार समेत विभिन्न विभागों में 30 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी।

विपणन विकास सहायता योजना से सेवा निर्यातकों को मिलेगी उड़ान, यूपी बना योजना लागू करने वाला पहला राज्य

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने सेवा क्षेत्र के निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। नई उप्र निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025–30 के तहत पहली बार सेवा निर्यातकों के लिए समर्पित विपणन विकास सहायता योजना लागू की गई है। इससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उपस्थिति मजबूत करने के लिए वित्तीय सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही यूपी देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सेवा निर्यात के लिए अलग और विशेष विपणन सहायता नीति लागू की है। यह योजना प्रदेश की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ रोजगार और निवेश के नए अवसर बनाएगी। योजना का लाभ उन्हीं सेवा निर्यातकों को मिलेगा जो निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो यूपी और उप्र निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकृत हों। साथ ही भारत सरकार द्वारा चिह्नित 12 चौंपियन सेवा क्षेत्रों के तहत निर्यात कर रहे हों और यूपी से उत्पन्न सेवाओं का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार–प्रसार कर रहे हों। ऑनलाइन करना होगा आवेदन योजना में आवेदन ऑनलाइन होंगे। निर्यातक इकाइयों को मेला समाप्त होने की तिथि से 120 दिनों में आवेदन करना होगा। पात्र दावों के निस्तारण के बाद धनराशि डीबीटी से सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। स्टॉल किराये के व्यय का 75 फीसदी (अधिकतम 2 लाख रुपये) तथा एक व्यक्ति की इकोनॉमी क्लास हवाई यात्रा पर व्यय का 75 प्रतिशत (अधिकतम 1 लाख रुपये) दिया जाएगा। देश में हुए अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी पर स्टॉल किराये के लिए अधिकतम 50 हजार और यात्रा व्यय पर 25 हजार रुपये तक दिए जाएंगे। विदेश में व्यापार मेलों, प्रदर्शनी और बायर सेलर मीट पर आयोजक संस्थाओं को कुल व्यय का 75 फीसदी अधिकतम एक करोड़ रुपये तक दिए जाएंगे। देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऐसे आयोजनों के लिए अधिकतम 75 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। इस श्रेणी में न्यूनतम 20 सेवा निर्यातक इकाइयों की भागीदारी जरूरी होगी।

आज के दौर में वायु शक्ति निर्णायक बन चुकी है, वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन में बोले राजनाथ सिंह

दिल्ली ब्यूरो

दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि आज के समय में वायु शक्ति युद्ध का निर्णायक हथियार बन चुकी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की उच्च–प्रभाव वाली सैन्य क्षमता को दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से दिखाया है। इस अभियान के दौरान आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने और उसके बाद पाकिस्तान की श्गैर–जिम्मेदाराना प्रतिक्रियाश से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उन्होंने भारतीय वायुसेना (आईएएफ) की सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर से मिले अहम सबक राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने साहस, तेजी और सटीकता के साथ आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया। उन्होंने कहा कि दुश्मन की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं को गहराई से समझना बहुत जरूरी है, ताकि भारत हमेशा निर्णायक बढ़त बनाए रख सके। उन्होंने वायुसेना के शीर्ष कमांडरों से आग्रह किया कि वे इस ऑपरेशन से मिले सबकों को आत्मसात करें और भविष्य की हर चुनौती के लिए सतर्क और तैयार रहें। जनता का भरोसा दिखाता है देश का आत्मविश्वास रक्षा मंत्री ने कहा, आमतौर पर जब दुश्मन हमला करता है, तो लोग डर जाते हैं। लेकिन जब पाकिस्तानी बलों ने भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, तब भी देश की जनता शांत रही और अपने रोजमर्रा के काम करती रही। उन्होंने इसे भारतीयों का सेनाओं की तैयारियों पर अटूट विश्वास बताया। वायु शक्ति अब केवल सामरिक नहीं, रणनीतिक हथियार राजनाथ सिंह ने कहा कि रूस–यूक्रेन युद्ध, इस्राइल–हमास संघर्ष, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे उदाहरण साबित करते हैं कि वायु शक्ति आज निर्णायक भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि वायु शक्ति केवल एक सामरिक साधन नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक उपकरण है। इसकी सबसे बड़ी ताकत गति, आश्चर्य और झटका देने की क्षमता है। उन्होंने कहा वायु शक्ति किसी भी नेतृत्व को यह क्षमता देती है कि वह दुश्मन को साफ़ संदेश दे सके कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाया जाएगा। 21वीं सदी का युद्धरू हथियारों से आगे की लड़ाई रक्षा मंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का युद्ध केवल हथियारों का नहीं, बल्कि विचारों, तकनीक और अनुकूलन क्षमता का युद्ध है। उन्होंने बताया कि साइबर युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ड्रोन और मानवरहित विमान, उपग्रह आधारित निगरानी और अंतरिक्ष आधारित क्षमताए भविष्य के युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सटीक हथियार, रियल–टाइम खुफिया जानकारी और डेटा आधारित निर्णय अब विकल्प नहीं, बल्कि आधुनिक युद्ध की बुनियादी जरूरत बन चुके हैं। त्रि–सेवा तालमेल और सुदर्शन चक्र राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को तीनों सेनाओं के बीच उत्कृष्ट तालमेल का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि थल, जल और वायु सेनाओं के बीच साझा समन्वय देश की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस पर घोषित श्सुदर्शन चक्रश भविष्य में राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। स्वदेशी जेट इंजन राष्ट्रीय मिशन रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी जेट इंजन का विकास अब एक राष्ट्रीय मिशन बन चुका है और सरकार इसे पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जो देश तकनीक, दूरदर्शी रणनीति और बदलते हालात के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता में महारत हासिल कर लेते हैं, वही वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ते हैं।

प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में नहीं लागू होगा एसआईआर, याचिका हाईकोर्ट से खारिज

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका को सारहीन कहकर खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश संत कबीर नगर के नरेंद्र कुमार त्रिपाठी की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं है। कहा कि एसआईआर प्रक्रिया 18 जुलाई 2025 से ही प्रारंभ हो चुकी है और इसकी अस्थायी मतदाता सूची 23 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की जानी है। ऐसे में मात्र इस आधार पर कि लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के लिए जारी दिशा–निर्देश पंचायत चुनावों पर भी लागू किए जाएं, इसमें न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका को सारहीन करार देकर खारिज कर दिया। पंचायत चुनाव की सूची में बढ़े 40 लाख से ज्यादा मतदाता पंचायत चुनाव के लिए कराए गए मतदाता पुनरीक्षण अभियान में 18196367 नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। अभियान में 14176809 मतदाताओं के नाम हटाए भी गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त आरपी सिंह ने बताया कि पुनरीक्षण में पिछली मतदाता सूची की अपेक्षा 4019558 (3.26 फीसदी) मतदाता बढ़े हैं। पत्रकारों से बृहस्पतिवार को बातचीत में उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण से पहले पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में 122950052 वोटर थे। अब ये संख्या 126969610 हो गई है। उन्होंने बताया कि जो नाम काटे गए हैं उनमें मृत, विस्थापित व डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक 5367410 डुप्लीकेट मतदाता थे। आंकड़ों के मुताबिक 18 से 23 वर्ष के ऐसे लोग जो पहली बार वोटर बने उनकी संख्या 1.05 लाख रही। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान नए वोटरों को जोड़ने को प्राथमिकता दी गई। ये भी सुनिश्चित किया गया कि कोई भी अयोग्य वोटर सूची में न रहे। तराई के जिलों में सबसे अधिक मतदाता बढ़े हैं।

1.5 करोड़ की कोकीन और 67 लाख के सोना के साथ दो गिरफ्तार

दिल्ली ब्यूरो

दिल्ली। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत–बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ की 149वीं बटालियन ने बड़ी जब्ती की है। खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बीएसएफ जवानों ने 316 ग्राम कोकीन जब्त की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दूसरी ओर, नदिया में बीएसएफ ने कार्रवाई करते हुए 67 लाख रुपए का सोना जब्त कर दो लोगों को गिफ्तार किया है। दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया बीएसएफ के अनुसार, 149वीं बटालियन की लावंगोला सीमा चौकी के जवानों को सूचना मिली थी कि चार बिनपाड़ा गांव में एक संदिग्ध के घर के पास मादक पदार्थ छिपाकर रखा गया है। इस इनपुट के आधार पर बीएसएफ ने तलाशी अभियान चलाया। गांव के दो गवाहों की मौजूदगी में संदिग्ध घर और आसपास के इलाके की गहन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान घर से लगभग दो मीटर की दूरी पर एक संदिग्ध पैकेट बरामद किया गया। पैकेट खोलने पर उसमें कोकीन पाई गई। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। जब्त की गई कोकीन को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है। 67 लाख रुपए का सोना को साथ दो गिरफ्तार बीएसएफ दक्षिण बंगाल सीमांत के जवानों ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भारतदृ बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित 32वीं वाहिनी की सीमाचौकी मालुआपारा क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए दो भारतीय तस्करों को गिरफ्तार कर सोना तस्करी नेटवर्क को करारा झटका दिया। कार्रवाई के दौरान तस्करों के कब्जे से 510 ग्राम वजनी सोने के बिस्कुट बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 67,37,100 लाख रुपए बताई गई है। बीएसएफ से कैसे की गिरफ्तारी जानकारी के मुताबिक बुधवार की सुबह सीमाचौकी मालुआपारा के जवानों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ तस्कर बांग्लादेश से तस्करी किया गया अवैध सोना सीमा चौकी क्षेत्र के रास्ते भारत में प्रवेश कराने की योजना बना रहे हैं। सुबह लगभग 10 बजे जवानों ने बांस की झाड़ियों की आड़ लेकर बांग्लादेश की ओर से भारत की सीमा की तरफ बढ़ते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। जवानों द्वारा चुनौती दिए जाने पर उक्त व्यक्ति ने बिना किसी प्रतिरोध के तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। इसके तुरंत बाद उसकी गहन तलाशी ली गई, जिसके दौरान उसके कब्जे से प्लास्टिक में लिपटे दो पैकेट बरामद किए गए। पैकेटों की जांच करने पर उनके अंदर से सोने के चार बिस्कुट पाए गए। जवानों ने मौके पर ही सोने के बिस्कुटों सहित तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसे यह खेप अपने गांव के ही एक व्यक्ति को सौंपनी थी। इस सूचना पर बीएसएफ जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रंगियापोटा गांव में छापा मारकर उसकी निशानदेही पर दूसरे तस्कर को उसके घर से हिरासत में ले लिया। इसके बाद दोनों को सीमा चौकी मालुआपारा लाकर पूछताछ की गई, जहां उन्होंने स्वीकार किया कि इस अवैध गतिविधि के बदले उन्हें रकम देने का वादा किया गया था। बीएसएफ की सतर्कता से यह तस्करी प्रयास समय रहते विफल कर दिया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्करों को जब्त सोने के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है।

संक्षिप्त समाचार

घने कोहरे से उत्तर, पूर्वी भारत में उड़ानें प्रभावित... एयरलाइनों ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी

एजेंसी

नयी दिल्ली। घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण दिल्ली, चंडीगढ़, पटना और उत्तर व पूर्वी भारत के अन्य हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन प्रभावित होने के बीच कई एयरलाइनों ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। एयर इंडिया ने चेताया है कि अगले कुछ दिनों में घना कोहरा दिल्ली और कई अन्य हवाई अड्डों पर परिचालन सेवा को प्रभावित कर सकता है, जिसका संभावित प्रभाव इसके पूरे नेटवर्क पर पड़ सकता है। एयरलाइन ने कहा, आपकी यात्रा की बेहतर योजना में मदद करने के लिए, विशेष रूप से त्यौहारों के सीजन दौरान, हमारा अनुरोध है कि आप एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस को अच्छी तरह से देख लें।

एक्मे सोलर को बड़ा बूस्ट : 4,725 करोड़ की मिली फंडिंग, सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक कंपनी एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रमुख भारतीय वित्तीय संस्थानों से 4,725 करोड़ रुपये का वित्तपोषण हासिल किया है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि इसमें परियोजनाओं के लिए 18 से 20 वर्ष की अवधि की वित्तपोषण और पुनर्वित्तपोषण व्यवस्थाएं शामिल हैं। बयान के अनुसार, एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड (एक्मे सोलर) ने अपनी अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने और वित्तपोषण लागत को कम करके अपनी पूंजी संरचना को अनुकूलित करने के लिए प्रमुख भारतीय वित्तीय संस्थानों से 4,725 करोड़ रुपये का ऋण समझौता हासिल किया है।

श्रम संहिताएं रोजगार को संगठित रूप देंगी, निरीक्षकों की भूमिका सुविधा प्रदान करने वाली : मांडविया

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में लागू किए गए श्रम कानून के 'मनमाने तरीके से नौकरी पर रखने व निकालने' और 'इंस्पेक्टर राज' को बढ़ावा देने की चिंताओं को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया और कहा कि नए कानून रोजगार को संगठित रूप देंगे जबकि निरीक्षक चीजों को सुगम बनाने की भूमिका निभाएंगे। नए नियमों के तहत, 300 कर्मचारियों वाली इकाइयों में छंटनी, कर्मचारियों की कटौती एवं इकाइयों को बंद करने के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पहले 100 कर्मचारियों वाली इकाइयों को ऐसी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। मांडविया ने कहा, '' हमने देश में रोजगार को संगठित रूप दिया है और प्रति इकाई श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर 300 कर दी है, जो पहले 100 थी।'' उन्होंने कहा कि पहले नियोक्ता कानूनी झंझटों से बचने के लिए 100 श्रमिकों को औपचारिक रोजगार देते थे और बाकी को असंगठित रूप से नियोजित करते थे। मांडविया ने कहा कि नए नियमों ने इन बचे हुए श्रमिकों के रोजगार को संगठित रूप दे दिया है और उन्हें वे सभी लाभ मिलेंगे जो एक पंजीकृत कर्मचारी को मिलते हैं। अनुपालन का बोझ बढ़ाकर 'इंस्पेक्टर राज' को बढ़ावा देने की चिंताओं पर उन्होंने स्पष्ट किया कि निरीक्षक किसी उद्योग के काम में बाधा डालने वाला नहीं बल्कि सुविधादाता होगा।

संपादकीय

मेसी से सीखें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना क्या है

दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल के भगवान कहलाने वाले लियोनल मेसी की भारत यात्रा ने दीवानगी के नए कीर्तिमान स्थापित करने के साथ ही विवाद भी खड़े किए। कोलकाता, हैदराबाद, मुम्बई, दिल्ली में स्टेडियम तो भरे रहे, पर साथ ही फिल्मी सितारों, राजनीतिज्ञों व उद्योगपतियों में इस वैश्विक सितारे के इर्द–गिर्द मंडराने की होड़ लगी रही। कोलकाता तो अपने फुटबॉल प्रेम के लिए विख्यात है। साल्ट लेक स्टेडियम पर अपर्याप्त व्यवस्था के चलते अफरा–तफरी मच गई। जिन दर्शकों ने 25000 रुपए तक में टिकट खरीदे थे, वे मेसी की एक झलक भी न पा सके। उन्होंने अपने को ठगा हुआ महसूस किया। राजनीति व फिल्म–जगत के सितारे तो मेसी के साथ फोटो खिंचवाते रहे, पर फुटबॉल के सच्चे प्रेमी दर्शक अपने सितारे को देख भी न सके। नाराज दर्शकों ने तोड़–फोड़ शुरू कर दी और ममता सरकार को भारी बदध्नामी झेलनी पड़ी, क्योंकि मेसी 20 मिनट में ही वापस चले गए। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शतद्रु दत्ता सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया व एसआईटी की जांच बैठा दी गई। मुख्यमंत्री ने माफी भी मांगी। होना तो यह चाहिए था कि मेसी को एक खुली जीप या गाड़ी में बैठाकर स्टेडियम का चक्कर और फुटबॉल को किक लगवा लेना था। दर्शक तृप्त हो जाते। कोलकाता में दर्शक न तो शाहरुख खान को देखने आए थे और न ही अन्य सितारों व राजनीतिज्ञों को। अलबत्ता कोलकाता के बाद हैदराबाद, मुम्बई व नई दिल्ली में टूर व्यवस्थित रहा। मुम्बई में जब मेसी की अगवानी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने की तो दोनों का भावुक मिलन व जर्सियों का आदान–प्रदान देख दर्शक तृप्त हो गए। मेसी के साथ लुई सुआरेज व रोड्रिगो डीश्पॉल भी थे और भारतीय लोकप्रिय फुटबॉलर सुनील छेत्री जब उनसे मिले तो सभी अभिभूत रह गए। भारत फुटबॉल में विश्व में 142वें स्थान पर है, पर इसके बावजूद फुटबॉल का जुनून उमड़ता नजर आया। मैसेज साफ था कि मेसी एक खिलाड़ी व व्यक्ति से ऊपर उठकर एक वैश्विक 'ब्रांड' बन गए हैं। आप 'सुपरस्टार' संस्कृति से छुटकारा पा ही नहीं सकते। खेल को कायम रखने व दर्शकों को निरंतर आकर्षित करते रहने की ताकत के कारण ऐसे सितारों की जरूरत भी रहती है। लेकिन भारत के ओलिंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने इस आयोजन के प्रति निराशा जाहिर की कि इससे भारत को क्या हासिल हुआ? इतने धन से तो भारतीय खेलों के विकास को गति मिल सकती थी। यहां मैं बिंद्रा से असहमत हूं। महान खिलाड़ी देश व सीमा से परे होते हैं। कला हमेशा कालजयी होती है। मेसी, पेले, तेंदुलकर, गावस्कर, ध्यानचंद, ब्रैडमेन जैसे खिलाड़ी दुनिया की धरोहर होते हैं। हुनर, कला व प्रतिभा का सम्मान ही स्वस्थ समाज व दुनिया की रचना करता है। अगर लियोनल मेसी को देखकर भारतीय युवा प्रेरित होते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? महान खिलाड़ी अपने देश व स्वाभिमान का प्रतीक भी होता है। उसका व्यवहार, विनम्रता व चरित्र दूसरों को प्रेरित करता है। मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं तो उन्होंने अपनी मातृभाषा स्पैनिश में ही बात की। लेकिन हमारे मशहूर खिलाड़ी विदेश जाते हैं तो हिंदी या अपनी मातृध्भाषा में बात करने से कतराते हैं। अपनी भाषा के सम्मान को अपने देश की संस्कृति व स्वाभिमान को कायम रखने का प्रयास कहा जा सकता है। मेसी को देखकर लगा कि वे अपने देश के सच्चे राजदूत हैं। हां, किसी महान खिलाड़ी के आगमन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मेसी से फुटबॉल और दूसरे खेलों के दिग्गज खिलाड़ियों का मिलना तो सौहार्द और प्रेरणा देने वाली बात है, पर फिल्मी सितारों और राजनीतिज्ञों का क्या काम था? बहरहाल, भारत के लोकप्रिय क्रिकेट–सितारे महेंद्रसिंह धोनी या विराट कोहली भी मेसी की तरह अपना 'ब्रांड' विश्व पटल पर स्थापित कर सकते हैं। वर्ष के आरम्भ में एनबीए स्टार लेब्रॉन जेम्स और करी ने चीन का एकल दौरा किया था। जेम्स के दौरे को 'नाइकी' ने स्पॉन्सर किया था और उसे द फॉरएवर किंग टूर का नाम दिया था। लियोनल मेसी इस कड़ी में और आगे बढ़ गए हैं, जिसमें ब्रांड 'व्यक्ति' से भी बड़ा धन बन जाता है। इसीलिए तो उन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ('गोट') कहा जाता है। हमारे खिलाड़ी विदेश जाते हैं तो मातृध्भाषा में बात करने से कतराते हैं। अपनी भाषा के सम्मान को संस्कृति व स्वाभिमान को कायम रखने का प्रयास कहा जा सकता है। मेसी को देखकर लगा वे स्पैनिश के सच्चे राजदूत हैं।

राशिफल

मेष :– काफी दिनों से अवरोधित कोई हल होने के आसार बनेंगे। जीवन साथी के स्वास्य के प्रति सतर्कता अपेक्षित है। शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में किया गया प्रयत्न सार्थक होगा। रोजगार में लाभकारी अवसर मिलेंगे।

बृषभ :– भावुकता व्यावहारिक जगत के अनुकूल चलने में बाधक होगी। अतः व्यवहार कुशल बने। भविष्य संबंधी कुछ चिंताएं मन पर प्रभावी होंगी। विद्यार्थी शिक्षा में लापरवाही न बरतें। घर में खुशहाल वातावरण रहेगा।

मिथुन :– मूल्यवान समय को व्यर्थ के कायरें में जाया न करें। नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी। सकारात्मक सोच को अपनाते हुए जीवन को सही दिशा की ओर केंद्रित करें और परिवार के अनुकूल चलें।

कर्क :– नये व्यावसायिक संबंध प्रगाढ़ होंगे। संवेदनशील शरीर ग्रहां की प्रतिकूलता से बीमार पड़ सकता है। महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति में असमर्थता जैसी स्थिति मन को निराश करेगी। पुरानी घटनाओं से मन को कष्ट संभव।

सिंह :– नयी घरेलू जिम्मेदारियों के पैदा होने से व्यय संभव। अच्छे कायरें से परिजनों के दिल में जगह बनायें। योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। महत्वपूर्ण कायरें में लापरवाही कतई न करें।

कन्या :– जीवनसाथी के स्वास्य के प्रति सचेत रहें। नये कायरें के क्रियान्वयन हेतु प्रयत्न तीव्र होगा। नये क्षेत्रों में प्रयास से लाभ संभव। व्यावसायिक यात्रा द्वारा लाभ होगा। संबंधियों के सहयोग से कठिनाइयां दूर होंगी।

तुला :– भविष्य को लेकर मन नकारात्मक आशंकाओं से प्रभावी रहेगा। प्रतिभाओं के बावजूद भी हीन भाव प्रतिभाओं के लाभ से वंचित करेगा। सुख–साधनों की लालसा बढ़ेगी। रोजगार में व्यस्तता रहेगी।

वृश्चिक :– रोजगार संबंधी कुछ नयी योजनाओं पर मन केंद्रित होगा। किसी कार्य में सफलता से उत्साह में वृद्धि होगी। कल्पनाओं में जीना छोड़ भौतिक जगत के अनुकूल चलने का प्रयत्न करें। भौतिक सुख में वृद्धि होगी।

धनु :– अपनी बातूनी कला का लाभ उठाएंगे। महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति में असमर्थता जैसी स्थिति मन को निराश करेगी। परिश्रम से आर्थिक लाभ का योग है। समस्याओं के समाधान से उत्साह में वृद्धि होगी।

मकर :– बीती बातों को सोचने के बजाय वर्तमान में जीने की चेष्ठा करें। जरूरत से ज्यादा बोलना व्यक्तित्व पर कुप्रभावी होगा। अतरू इसे सुधारें। नीरस स्वभाववश रचनात्मक योजनाओं को सार्थक करने में असमर्थ होंगे।

कुंभ :– सब कुछ सामान्य होते हुए भी मन अरुचि का शिकार होगा। थोड़ा संयमी व धैर्यवान बने। भाग्य से प्राप्त सभी स्थितियों के मध्य समझौतावादी रवैया अपनायें। कुछ नई व्यस्तताएं सामने आएंगी। आलस्य कतई न करें।

मीनः– कुछ व्यासायिक कारणों से घर से दूर रहना पड़ सकता है। परिजनों की सुख–सुविधा के प्रति मन चिंतित होगा। मस्त–मौला मन ब्यर्थ के कायरे में समय जाया कर महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाह के प्रति मन चिंतित होगा। मस्त–मौला मन ब्यर्थ के कायरे में समय जाया कर महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाह होगा।

सड़क हादसों की बढ़ती वजह : अवैध पार्किंग और हाईवे किनारे ढाबे

–सुनील कुमार महला

सड़क हादसे एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी हैं, जो पल भर में हँसते–खेलते परिवारों को उजाड़ देती हैं। इनमें किसी अपने की जान जाना या जीवन भर की अपंगता पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल देती है। हादसे के बाद केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं होता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक पीड़ा भी लंबे समय तक बनी रहती है। बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है और बुजुर्ग सहारे से वंचित हो जाते हैं। समाज पर भी इसका व्यापक असर पड़ता है, क्योंकि कार्यशील नागरिकों की क्षति से सामाजिक–आर्थिक विकास बाधित होता है। अस्पतालों और आपात सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इन हादसों का सबसे दुखद पहलू यह है कि अधिकांश दुर्घटनाएं थोड़ी–सी सावधानी और नियमों के पालन से रोकी जा सकती हैं। इसलिए सड़क सुरक्षा को केवल कानून नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में समझना बेहद जरूरी है। घना कोहरा व धुंध सड़क हादसों का प्रमुख कारणः–

हाल ही में यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के पास 16 दिसंबर 2025 मंगलवार तड़के कोहरा 13 लोगों के लिए काल बन गया। दरअसल, कोहरे के कारण दृश्यता शून्य होने के कारण आपस में टकराने से वाहनों में आग लग गई, जिससे यात्री जिंदा जलकर मर गये। जानकारी के अनुसार हादसा इतना भीषण था कि सौ से अधिक लोग इसमें घायल हो गए। वास्तव में, घने कोहरे के कारण आगे चल रहा वाहन डिवाइडर से टकराकर संतुलन खो बैठा और इसके बाद पीछे से आ रहे वाहन एक के बाद एक टकराते चले गए। इससे वाहनों में आग लग गई। गहरी नींद में सो रहे यात्रियों की तेज आवाज से आंख खुली तो चीख–पुकार मच गई और वे जान बचाने के लिए जलते वाहनों से कूदने लगे। आशंका है कि सीएनजी वाहन में विस्फोट से आग लगी। दमकलों ने जब तक आग पर काबू पाया, 14 वाहन जल चुके थे। इनमें आठ बसें और एक कार शामिल है। ये बसें यूपी, बिहार, अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली आ रही थीं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि, श्मेरी संवेदनाएं अपनों को खोने वाले परिवारों के साथ हैं।श भीषण हादसे के बाद प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो–दो लाख और घायलों को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की गई है। वहीं, यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी मृतकों के परिजनों को दो–दो लाख और घायलों को 50–50 हजार की मदद देने का ऐलान किया है।

सड़क हादसों के लिए वाहन चालकों की लापरवाही ही जिम्मेदार नहींः–

हाल फिलहाल, यहां यह कहना ग़लत नहीं होगा कि हाल के दिनों में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस–वे पर जो बड़े सड़क हादसे हुए हैं, उनके लिए सिर्फ वाहन चालकों की लापरवाही ही जिम्मेदार नहीं है।सच तो यह है कि सड़क किनारे बने ढाबे और होटल भी इन दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण बन रहे हैं। अक्सर इन ढाबों के सामने ट्रक, बस या अन्य वाहन सड़क के किनारे खड़े कर दिए जाते हैं और सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ियां उन्हें समय पर देख नहीं पातीं और उनसे टकरा जाती हैं। इसका गंभीर उदाहरण कुछ समय पहले ही राजस्थान के फलोदी में हुआ एक हादसा है, जहां सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर से टेम्पो ट्रैवलर टकरा गया। मीडिया में आईं खबरों के अनुसार इस दुर्घटना में 10 महिलाओं और 4 बच्चों सहित कुल 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और सुनवाई के दौरान एनएचएआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (नेशनल हाइवेज अथारिटी ऑफ इंडिया)और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने साफ कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस–वे के किनारे बने अवैध ढाबे और होटल सड़क हादसों की बड़ी वजह हैं और इन्हें रोकने के लिए देशभर में लागू होने वाले नियम बनाने की जरूरत है। वास्तव में, असल समस्या यह है कि कई ढाबे और होटल लाभ कमाने के उद्देश्य से बिना पर्याप्त पार्किंग के ही सड़क किनारे खोल दिए जाते हैं और वहां ठहरने वाले लोग मजबूरी में अपनी गाड़ी सड़क पर खड़ी कर देते हैं, जबकि इन सड़कों पर वाहन बहुत तेज रफ्तार से चलते हैं। ऐसे में हादसों का खतरा लगातार बना रहता है। सवाल यह है कि ऐसे ढाबों को बिना नियम–कानून के चलने की इजाजत किसने दी और अब तक सरकार ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की ? क्या ऐसे ढ़ाबा व होटल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए ? यह विडंबना ही है कि आज हमारे देश में सड़क किनारे खुलने वाले ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल अक्सर बिना किसी ठोस नियम–कानून के संचालित हो रहे हैं। ये जहां जगह मिल गई, वहीं बना दिए जाते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है। अधिकांश ढाबों के सामने वाहनों की अवैध पार्किंग रहती है, या बहुत से स्थानों पर तो पार्किंग व्यवस्थाएं होतीं ही नहीं हैं, ऐसे में वाहनों को यत्र–तत्र अव्यवस्थित रूप से पार्क करना पड़ता है, जो सड़क हादसों का कारण बनती है। वास्तव में ऐसी जगहों पर न तो यहां सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था होती है और न ही प्रवेश–निकास के लिए निर्धारित स्थान। कई जगहों पर तो पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव देखने को मिलता है। इससे यात्रियों को, वाहन चालकों को परेशानी होती है और आसपास गंदगी भी फैलती है।यह एक कड़वा सच है कि स्वच्छता और सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी की जाती है। जरूरत है कि ऐसे ढाबों और होटलों के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाएं और उनका सख्ती से पालन कराया जाए।

आंकड़े बयां करते हैं सड़क हादसों की भयावहताः–

हाल फिलहाल, यदि हम यहां पर आंकड़ों की बात करें तो 2025 में भारत में सड़क हादसों की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। उपलब्ध सरकारी व मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जनवरी से जून 2025 के बीच केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही लगभग 67,900 से अधिक सड़क दुर्घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें करीब 29,000 लोगों की मौत हुई। यह आंकड़ा दर्शाता है कि हर दिन औसतन 150 से अधिक लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग, शराब पीकर वाहन चलाना, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और सड़क किनारे अव्यवस्थित ढाबे–पार्किंग जैसी समस्याएँ इन हादसों के प्रमुख कारण बने हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि यही रुझान जारी रहा, तो 2025 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की कुल संख्या पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को भी पार कर सकती है, जो सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। वास्तव में आज देश में सड़कें तो तेजी से बन रही हैं, लेकिन उन पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने को उतनी गंभीरता नहीं दी जा रही। हादसों के कारण बार–बार सामने आने के बावजूद ठोस नीति और सख्त नियम लागू नहीं किए जा रहे हैं। अगर समय रहते अवैध ढाबों, पार्किंग व्यवस्था और सड़क सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ऐसे हादसे आगे भी होते रहेंगे और देश को जान–माल का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन की जिम्मेदारी पूरे समाज की हैः–

बहरहाल, यहां यह भी कहना ग़लत नहीं होगा कि हमारे देश में दिसंबर–जनवरी ठंड के महीने होते हैं और इस दौरान देश के कई हिस्सों, विशेषकर पानी वाले इलाकों में घना कोहरा व धुंध छा जाती है, जिससे सड़क पर दृश्यता बेहद कम हो जाती है। ऐसे हालात में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतना अनिवार्य है। मोबाइल फोन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ध्यान भटकाता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ाता है। शराब या किसी भी प्रकार के नशे में वाहन चलाना जानलेवा साबित हो सकता है। यदि नींद या थकान महसूस हो रही हो तो वाहन रोककर विश्राम करना ही सुरक्षित विकल्प है। इसके साथ ही यातायात नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए, गति सीमित रखनी चाहिए और सीट बेल्ट अवश्य लगानी चाहिए, क्योंकि यह दुर्घटना की स्थिति में जान बचाने में अहम भूमिका निभाती है। वास्तव में,सावधानी और जिम्मेदारी ही ठंड व कोहरे के मौसम में सुरक्षित यात्रा की कुंजी है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि यह हमारे पूरे समाज की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। अधिकतर सड़क हादसे तेज़ गति, नशे में ड्राइविंग, मोबाइल फोन के प्रयोग और यातायात के नियमों की अनदेखी के कारण होते हैं। हेलमेट, सीट बेल्ट, लेन ड्राइविंग और ट्रैफिक संकेतों का पालन करने से दुर्घटनाओं में भारी कमी लाई जा सकती है। सड़कों की खराब स्थिति, अव्यवस्थित पार्किंग और अतिक्रमण भी हादसों को बढ़ावा देते हैं। सरकार, प्रशासन और नागरिकों सभी को मिलकर सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। जागरूकता अभियान, सख्त कानून और उनका ईमानदार क्रियान्वयन बेहद आवश्यक है। सुरक्षित सड़कें केवल नियमों से नहीं, बल्कि जिम्मेदार व्यवहार से बनती हैं। यदि समय रहते सावधानी बरती जाए, तो अनमोल जानें बचाई जा सकती हैं।

ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती यहूदी–विरोधी हिंसा : आंतरिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक संतुलन

–डॉ. सत्यवान सौरभ

ऑस्ट्रेलिया को लंबे समय तक एक ऐसे बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र के रूप में देखा गया है, जहाँ विविध धार्मिक, नस्ली और सांस्कृतिक समुदायों ने अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व का अनुभव किया। यहूदी समुदाय भी इस सामाजिक संरचना का एक सशक्त और सम्मानित हिस्सा रहा है। किंतु हाल के वर्षों में, विशेषकर 2023 के बाद, यहूदी संस्थानों, सभास्थलों और व्यक्तियों के विरुद्ध लक्षित हिंसा की घटनाओं में वृद्धि ने इस धारणा को गंभीर चुनौती दी है। आगज़नी, नफ़रत भरी ग्रैफिटी, धमकियाँ और हमलों की घटनाएँ केवल आपराधिक कृत्य नहीं हैं, बल्कि वे ऑस्ट्रेलियाई समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण, असहिष्णुता और असुरक्षा की गहरी परतों को उजागर करती हैं। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यहूदी–विरोधी हिंसा क्यों बढ़ रही है और राज्य आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए नागरिक स्वतंत्रताओं का संतुलन कैसे बनाए। यहूदी–विरोधी हिंसा के उभार को समझने के लिए सबसे पहले वैश्विक भूराजनीतिक संदर्भ पर ध्यान देना आवश्यक है। इज़राइल–ग़ाज़ा संघर्ष जैसे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम अब केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रह गए हैं। डिजिटल मीडिया और वैश्विक सूचना प्रवाह के कारण इनका प्रभाव दूरस्थ समाजों तक तत्काल पहुँचता है। ऑस्ट्रेलिया में भी इस संघर्ष ने भावनात्मक ध्रुवीकरण को जन्म दिया है, जहाँ विदेश नीति या सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना कई बार यहूदी समुदाय के सामूहिक दोषारोपण में बदल जाती है। राजनीतिक असहमति और धार्मिक–जातीय पहचान के बीच की यह रेखा धुंधली पड़ना यहूदी–विरोधी हिंसा को वैचारिक वैधता प्रदान करता है। इसके साथ ही चरमपंथी विचारधाराओं का विस्तार एक गंभीर कारक बनकर उभरा है। दक्षिणपंथी अतिवाद, श्वेत वर्चस्ववादी सोच और कुछ कट्टरपंथी नेटवर्क लंबे समय से यहूदियों को षड्यंत्र सिद्धांतों से जोड़ते रहे हैं। डिजिटल युग में इन विचारों का प्रसार तेज़ और व्यापक हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स और ऑनलाइन फ़ोरम ऐसे 'इको–चौम्बर्स' बनाते हैं, जहाँ नफ़रत को सामान्य व्यवहार की तरह प्रस्तुत किया जाता है। जब व्यक्ति लगातार एक ही प्रकार की भड़काऊ सामग्री देखता है, तो हिंसा धीरे–धीरे वैध और आवश्यक प्रतिक्रिया के रूप में चित्रित होने लगती है। दुष्प्रचार और साजिश कथाएँ भी यहूदी–विरोधी हिंसा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐतिहासिक रूप से यहूदियों को आर्थिक संकटों, महामारी और राजनीतिक अस्थिरता के लिए दोषी ठहराने की प्रवृत्ति रही है। आधुनिक समय में यही प्रवृत्ति सोशल मीडिया के माध्यम से नए रूप में सामने आती है। कोविड–19 महामारी, वैश्विक आर्थिक मंदी या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से जुड़ी जटिलताओं को यहूदी समुदाय से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। बार–बार दोहराए जाने पर ये झूठे आख्यान सामाजिक चेतना में स्थान बना लेते हैं और हिंसा के लिए मानसिक आधार तैयार करते हैं। आंतरिक सुरक्षा ढांचे की कुछ संरचनात्मक कमजोरियाँ भी इस समस्या को गहराती हैं। हाल की घटनाओं ने यह सवाल उठाया है कि हथियार लाइसेंसिंग प्रणाली, मानसिक स्वास्थ्य आकलन और खुफिया निगरानी कितनी प्रभावी है। यदि संभावित हिंसक प्रवृत्तियों के संकेत समय रहते पहचान में न आएँ, तो तथाकथित 'लोन वुल्फ' हमले गंभीर नुकसान पहुँचा सकते हैं। यह केवल पुलिस की विफलता नहीं, बल्कि निवारक शासन की चुनौती है, जहाँ जोखिमों का पूर्वानुमान और समय पर हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक होता है। इन परिस्थितियों में राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती आंतरिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की है। लोकतांत्रिक समाज में सुरक्षा का अर्थ केवल कठोर कानून और निगरानी नहीं हो सकता। राज्य की पहली जिम्मेदारी कानून के शासन को बनाए रखना है, जिसमें घृणा अपराधों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई शामिल है। यहूदी–विरोधी हिंसा के मामलों में सख़्त अभियोजन और दंड का स्पष्ट संदेश देना आवश्यक है कि समाज में नफ़रत और हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। साथ ही, पीड़ितों को न्याय और सहायता उपलब्ध कराना विश्वास बहाली के लिए अनिवार्य है। खुफिया तंत्र का समन्वय आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ है। संघीय और राज्य स्तर की एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने में देरी या असंगति संभावित खतरों को अनदेखा कर सकती है। ऑनलाइन कट्टरपंथ की निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों का विश्लेषण और समय रहते हस्तक्षेपकृये सभी उपाय आवश्यक हैं। किंतु यह निगरानी लक्षित और अनुपातिक होनी चाहिए। अंधाधुंध निगरानी न केवल नागरिकों की गोपनीयता का उल्लंघन करती है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास भी पैदा कर सकती है। डिजिटल स्पेस का शासन आज आंतरिक सुरक्षा का अनिवार्य घटक बन चुका है। ऑनलाइन घृणा भाषण और दुष्प्रचार को नियंत्रित किए बिना यहूदी–विरोधी हिंसा पर अंकुश लगाना कठिन है। इसके लिए प्लेटफ़ॉर्म जवाबदेही, पारदर्शी नियम और त्वरित कार्रवाई तंत्र आवश्यक हैं। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वैध राजनीतिक असहमति और शांतिपूर्ण विरोध को दबाया न जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल है और सुरक्षा उपायों को इसे कमजोर नहीं करना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण, किंतु अक्सर उपेक्षित पक्ष समुदाय सहभागिता है। यहूदी समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ विश्वास–आधारित संवाद सुरक्षा प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाता है। जब समुदाय स्वयं को राज्य का साझेदार महसूस करता है, तो वह संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने और कट्टरपंथी प्रभावों का प्रतिरोध करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। सामुदायिक नेताओं की भागीदारी, शिकायत निवारण तंत्र और पीड़ित सहायता सेवाएँ सामाजिक एकजुटता को मजबूत करती हैं। शिक्षा और सार्वजनिक विमर्श दीर्घकालिक समाधान की कुंजी हैं। यहूदी–विरोधी हिंसा की जड़ें केवल वर्तमान राजनीतिक घटनाओं में नहीं, बल्कि ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों में भी निहित हैं। होलोकॉस्ट शिक्षा, बहुसांस्कृतिक पाठ्यक्रम और अंतर–धार्मिक संवाद नफ़रत के विरुद्ध सामाजिक प्रतिरक्षा विकसित कर सकते हैं। मीडिया की भूमिका भी निर्णायक है। जिम्मेदार रिपोर्टिंग, तथ्यों की जाँच और भड़काऊ भाषा से परहेज़ सामाजिक तनाव को कम कर सकता है। यहूदी–विरोधी हिंसा के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया ऑस्ट्रेलिया के लोकतांत्रिक मूल्यों की भी परीक्षा है। यदि सुरक्षा उपाय किसी विशेष समुदाय को संदिग्ध ठहराने लगें या असहमति को कुचलने का माध्यम बन जाएँ, तो वे स्वयं समस्या का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए अधिकार–आधारित सुरक्षा दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें सुरक्षा और स्वतंत्रता को परस्पर पूरक माना जाए। विदेश नीति की आलोचना और यहूदी–विरोधी नफ़रत के बीच स्पष्ट अंतर करना इस संतुलन का केंद्रीय तत्व है। अंततः, ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती यहूदी–विरोधी हिंसा केवल कानून–व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह सामाजिक चेतावनी भी है। यह दिखाती है कि वैश्विक रुवीकरण, डिजिटल दुष्प्रचार और आंतरिक कमजोरियाँ मिलकर किस प्रकार लोकतांत्रिक समाजों को अस्थिर कर सकती हैं। इसका समाधान न तो केवल सख़्त कानूनों में है और न ही पूर्ण उदारता में, बल्कि संतुलित, अधिकार–सम्मत और समुदाय–केंद्रित रणनीति में निहित है। लक्षित पुलिसिंग, एकीकृत खुफिया तंत्र, जिम्मेदार डिजिटल नियमन और सामाजिक संवादकृइन सभी के माध्यम से ही नफ़रत अपराधों का प्रभावी मुकाबला किया जा सकता है। जब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएँ एक–दूसरे को सुदृढ़ करती हैं, तभी बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र वास्तव में सुरक्षित और टिकाऊ बन पाता है।

संसद का अवरुद्ध स्वर और लोकतंत्र की कसौटी

–डॉ. प्रियंका सौरभ

भारतीय संसद लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है। यही वह मंच है जहाँ जनता की विविध आकांक्षाएँ, असहमतियाँ और अपेक्षाएँ बहस के माध्यम से नीति और कानून का रूप लेती हैं। किंतु हाल के वर्षों में संसद की कार्यवाही बार–बार बाधित होने, प्रश्नकाल के स्थगित रहने, विधेयकों के बिना पर्याप्त चर्चा पारित होने और सदन के समय से पहले स्थगन ने इसकी गरिमा और प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। संसद, जो संवाद और सहमति का प्रतीक होनी चाहिए थी, वह अनेक अवसरों पर टकराव और अवरोध का अखाड़ा बनती दिखी है। यह स्थिति केवल संसदीय परंपराओं का क्षरण नहीं, बल्कि प्रतिनिधि लोकतंत्र की जड़ों के कमजोर होने का संकेत भी है। संसद में व्यवधान कोई नया विषय नहीं है। विरोध, असहमति और सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रतिपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में अनिवार्य है। किंतु जब विरोध का प्रमुख औजार निरंतर हंगामा, नारेबाजी और कार्यवाही ठप करना बन जाए, तब यह प्रश्न उठता है कि क्या संसद अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर पा रही है। बार–बार स्थगित होने वाली कार्यवाही का सबसे बड़ा नुकसान जनता को होता है, क्योंकि संसद का हर खोया हुआ घंटा नीतिगत विमर्श, जनहित के मुद्दों और विधायी समीक्षा से चूक का प्रतीक बन जाता है। यह स्थिति कार्यपालिका को अधिक शक्तिशाली बनाती है और विधायिका की निगरानी भूमिका को कमजोर करती है। लोकतांत्रिक शासन में संसद केवल कानून पारित करने की मशीन नहीं होती, बल्कि वह कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने, नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा करने और समाज के विभिन्न वर्गों की आवाज़ को सामने लाने का मंच भी होती है। जब संसद बाधित होती है, तब कार्यपालिका पर सवाल पूछने के अवसर कम होते हैं, अध्यादेशों और 'गिलोटिन' जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से विधायी निगरानी कमजोर पड़ती है और निर्णय कुछ सीमित हाथों में केंद्रित होने लगते हैं। इस संदर्भ में संस्थागत सुधारों की आवश्यकता केवल तकनीकी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक नैतिकता से जुड़ा प्रश्न है। संसदीय समितियों की भूमिका इस बहस में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में संसदीय समितियाँ सदन के बाहर अपेक्षाकृत शांत वातावरण में विधेयकों की बारीकी से जांच करने, विशेषज्ञों और हितधारकों की राय लेने तथा राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर व्यावहारिक सुझाव देने का मंच प्रदान करती हैं। जब अधिकाधिक विधेयकों को बिना समिति जांच के पारित किया जाता है, तो कानून निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। संस्थागत सुधार के रूप में सभी प्रमुख विधेयकों को अनिवार्य रूप से समितियों को भेजना न केवल विधायी प्रक्रिया को मजबूत करेगा, बल्कि संसद के भीतर होने वाले टकराव को भी कम कर सकता है, क्योंकि असहमति का समाधान बहस और प्रमाण के माध्यम से बाहर संभव होगा। प्रश्नकाल को संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है। यही वह समय होता है जब निर्वाचित प्रतिनिधि सीधे–सीधे मंत्रियों से जनता से जुड़े सवाल पूछते हैं और सरकार को अपने निर्णयों का स्पष्टीकरण देना पड़ता है। प्रश्नकाल का बार–बार बाधित होना या औपचारिकता में सिमट जाना कार्यपालिका की जवाबदेही को कमजोर करता है। संस्थागत सुधार के तहत प्रश्नकाल की सुरक्षा और उसकी अनिवार्यता तय करना आवश्यक है, ताकि किसी भी परिस्थिति में इसे स्थगित न किया जाए। इससे सरकार और विपक्ष दोनों को संवाद के लिए बाध्य होना पड़ेगा। संसद में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के लिए आचार–संहिता और दंडात्मक प्रावधान भी आवश्यक हैं। वर्तमान में नियम तो मौजूद हैं, किंतु उनका निष्पक्ष और सुसंगत क्रियान्वयन अक्सर विवादों में घिर जाता है। यदि सांसदों के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और सर्वसम्मति से तय आचार–संहिता हो तथा उसके उल्लंघन पर समान रूप से कार्रवाई हो, तो अव्यवस्थित आचरण पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। यह सुधार केवल दंड देने का नहीं, बल्कि संसदीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने का माध्यम बन सकता है। संसद के कार्यदिवसों की संख्या भी एक महत्वपूर्ण संस्थागत मुद्दा है। भारत की संसद कई विकसित लोकतंत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम दिन बैठती है। सीमित सत्रों में भारी विधायी एजेंडा न केवल सांसदों पर दबाव बढ़ाता है, बल्कि सार्थक बहस की संभावना को भी कम करता है। न्यूनतम निश्चित बैठक दिनों वाला कैलेंडर तय करना और उसका सख्ती से पालन करना विधायी गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। अधिक बैठकों का अर्थ केवल अधिक कानून नहीं, बल्कि अधिक संवाद, अधिक प्रश्न और अधिक जवाबदेही है। हालाँकि, इन संस्थागत सुधारों की राह आसान नहीं है। राजनीतिक दल अक्सर संसद के भीतर व्यवधान को एक वैध राजनीतिक हथियार मानते हैं। विपक्ष को यह आशंका रहती है कि सुधारों के नाम पर उसके विरोध के अधिकार को सीमित किया जाएगा, जबकि सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगता है कि वह संस्थागत नियमों का उपयोग असहमति को दबाने के लिए कर सकता है। इसके अतिरिक्त, स्पीकर या सभापति की निष्पक्षता पर उठने वाले सवाल भी सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा बनते हैं। यदि पीठासीन अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगे, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी विवाद का कारण बन जाती है।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूरी तरह से दिग्भ्रमित: ब्रजेश पाठक

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा सुप्रीमो पर किया कड़ा प्रहार
पीडीए सच में है पर्सनल डेवलपमेंट एसोसिएशन: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले: कुर्सी की भूख अखिलेश को झूठ बोलने पर करती है मजबूर

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर कड़ा प्रहार किया है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जिस पीडीए की चर्चा करते हैं, वह वास्तव में पर्सनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरी तरह दिग्भ्रमित हो चुके हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव सच्चाई को देखकर भी सच नहीं कह सकते, क्योंकि कुर्सी की भूख उन्हें झूठ बोलने पर मजबूर करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार जनता को गुणवत्तापूर्ण जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है और उसी दिशा में लगातार तेजी से काम किया जा रहा है।

डेवलप्ड स्टेट के रूप में तेजी से परिवर्तित हो रहा उत्तर प्रदेश

ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के वर्तमान आंकड़ों को देखते होंगे, राउंड द क्लॉक बिजली आपूर्ति, बेहतर कनेक्टिविटी, जीवन स्तर में सुधार और सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं, तो उन्हें निश्चित रूप से आश्चर्य होता होगा। स्वाभाविक है कि वे इन उपलब्धियों की तुलना अपने शासनकाल से करते होंगे, जब प्रदेश में टूटी सड़कें थीं, रात में अंधेरा रहता था, अस्पतालों को तबेला बना दिया गया था और स्कूलों में न बाउंड्री वॉल थी और न ही पढ़ाई का माहौल।उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह बदल चुका है और एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदूषण के आंकड़ों पर उठाए जा रहे सवालों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आईआईटी द्वारा लगाए गए सेंसर से ही रीडिंग ली जाती है, जिनमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।

पुलिस और एसटीएफ ने सभी घटनाओं का किया निष्पक्ष अनावरण

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश की जनता भली–भांति जानती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने हर घटना का निष्पक्ष और प्रभावी अनावरण किया है। एसटीएफ द्वारा कुख्यात अपराधियों को ढेर किया जा चुका है, जो संगठित माफिया गिरोह के रूप में प्रदेश में सक्रिय थे।उन्होंने कहा कि चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो या बद्दो जैसे कुख्यात अपराधी, अंतरराज्यीय गैंग चलाने वाले माफियाओं का उत्तर प्रदेश से पूरी तरह सफाया हो चुका है। अब प्रदेश में कोई माफिया नहीं है। माफिया दुम दबाकर प्रदेश से भाग चुके हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि आप उन्हीं माफियाओं के समर्थक थे और उन्हीं के सहारे सत्ता चला रहे थे। आज उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है और उसने समाजवादी पार्टी के खाते को बंद कर दिया है।

समाजवादी पार्टी को नहीं है कुछ भी कहने का अधिकार

ब्रजेश पाठक ने पुलिस भर्ती और लेखपाल भर्ती का उल्लेख करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को इन विषयों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में भर्तियों में जातिवाद और भाई–भतीजावाद के गंभीर आरोप लगते थे। एसडीएम जैसे 86 पदों में से 56 नियुक्तियां एक ही जाति की थीं। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में लेखपाल भर्ती के दौरान पर्ची सिस्टम चलता था, जबकि वर्तमान सरकार में 8,085 पदों पर पूरी तरह मेरिट और बुद्धि कौशल के आधार पर नियुक्तियां की गई हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन भर्तियों पर सवाल उठाना उन हजारों युवाओं की मेधा और प्रतिभा पर सवाल उठाने जैसा है।

केवल बयानवीर बनना है लक्ष्य

ब्रजेश पाठक ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में लाखों नौकरियों में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की है। एक भी भर्ती में गड़बड़ी नहीं हुई है और आरक्षण के सभी नियमों का पूर्ण पालन किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 68 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को भू माफियाओं से मुक्त कराया है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य केवल बयानबाजी करना रह गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार इसे निर्धारित नहीं करती। यह मौसम विभाग और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा तय किया जाता है। सरकार सभी मानकों के अनुरूप कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। सभी जिलों को फोरलेन से जोड़ने का कार्य किया गया है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में हैं और निवेश के मामले में भी यूपी देश में अग्रणी है।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक दिवस पर संवाद कार्यक्रम, सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक दिवस के अवसर पर इनिशिएटिव फाउंडेशन इंडिया द्वारा अंसल ग्रीन ऑर्किड अपार्टमेंट्स, सेक्टर–एम, आशियाना, लखनऊ में एक विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना तथा ठोस नीतिगत हस्तक्षेप की मांग करना रहा। संवाद के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आज भी बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक शोषण, अत्याचार, कर्ज, फर्जी एजेंटों, बिना लिखित रोजगार अनुबंध, बीमा के अभाव तथा विदेशों में कमजोर सहायता तंत्र जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रतिभागियों ने सवाल उठाया कि जब प्रवासी श्रमिक देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो उनकी सुरक्षा और अधिकारों की प्रभावी व्यवस्था अब तक क्यों नहीं बन पाई है। संवाद कार्यक्रम में इनिशिएटिव फाउंडेशन इंडिया के निदेशक श्री अमित मिश्रा ने कहा प्रवासी श्रमिक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सुरक्षित और कानूनी प्रवासन उनका अधिकार है, कोई विकल्प नहीं। सवाल यह है कि इसे ज़मीनी स्तर पर अब तक क्यों सुनिश्चित नहीं किया गया। सऊदी अरब से लौटे प्रवासी श्रमिक अरशद ने कहा विदेश जाने से पहले सही जानकारी और कानूनी प्रक्रिया के अभाव में श्रमिक बड़ी परेशानियों में फँस जाते हैं। यह व्यवस्था आज भी कमजोर क्यों है, यही सबसे बड़ा सवाल है। यूएई में कार्यरत श्रमिक श्याम की पत्नी रीना ने कहा जब परिवार का सदस्य विदेश जाता है तो पूरा परिवार असुरक्षा में जीता है। संकट के समय न जानकारी मिलती है, न सहायता। यह स्थिति बदलनी चाहिए। सामाजिक एवं श्रम विशेषज्ञ अब्दुल राज ने कहा प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा केवल योजना का विषय नहीं, बल्कि अधिकार और जवाबदेही का प्रश्न है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, शोषण समाप्त नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में शालिनी, संध्या, अर्चना, हनीफ, रहनुमा, प्रवीन, शिराज, आशुतोष, नवीन सहित दर्जनों प्रवासी श्रमिकों ने एक स्वर में सुरक्षित, सम्मानजनक एवं अधिकार–आधारित प्रवासन की मांग की तथा सरकार से तत्काल ठोस कदम उठाने का आह्वान किया।

महिला उद्यमियों के लिए टेक्नोलॉजी आधारित ट्रेनिंग प्रोग्राम,जुटीं आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में गुरुवार को राज्य आजीविका मिशन और डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आजीविका मिशन से जुड़ी महिला उद्यमियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान महिलाओं को उद्यम विकास, तकनीकी नवाचार और उत्पादन बढ़ाने से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद महिला उद्यमियों ने अपने–अपने अनुभव साझा किए। महिलाओं ने बताया कि आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद उन्हें स्वरोजगार के नए अवसर मिले

हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। प्रशिक्षण सत्र के दौरान महिलाओं ने उत्पादन, विपणन और संसाधनों के बेहतर उपयोग से जुड़ी अपनी चुनौतियां भी सामने रखीं। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स के सीईओ ने बताया कि उनकी संस्था प्रदेश के 10 जिलों में गवर्नमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और राज्य आजीविका मिशन के सहयोग से 'हाईजेक' कार्यक्रम के तहत काम कर रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आधुनिक तकनीक के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता दोनों को बढ़ा सकें। आयोजकों की माने तो, इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं को तकनीकी जानकारी के साथ–साथ बाजार की समझ भी प्रदान करते हैं।

संक्षिप्त

भक्ति के रंग में रंगेगा सदर, कैंट में 22 दिसंबर से श्रीमद्भागवत कथा

संवाददाता, लखनऊ। नवाबों के शहर लखनऊ की फिजाओं में अब भक्ति और आध्यात्म की सुगंध घुलने वाली है। सदर कैंट स्थित पौराणिक श्री शिव श्याम मंदिर (हाता राम दास) के प्रांगण में आगामी 22 दिसंबर से 29 दिसंबर तक श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का विराट आयोजन होने जा रहा है। श्री शिव श्याम मंदिर समिति के मुख्य संयोजक राजेन्द्र पांडेय गुरुजी ने बताया कि कथा पूर्व 21 दिसंबर (रविवार) को प्रातः 10.30 बजे एक विशाल मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर मंदिर परिसर से निकलेंगी, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। उन्होंने बताया कि 22 दिसम्बर से 29 दिसम्बर तक शाम 4 बजे से कथा व्यास आचार्य विष्णु शरण भारद्वाज जी महाराज अपनी ओजस्वी और मधुर वाणी से भक्तों को श्रीमद्भागवत के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराएंगे।

सपा महिला नेताओं का नीतीश कुमार–संजय निषाद के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस से हुई नोकझोंक

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर सपा महिला नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा सरकार में मंत्री संजय निषाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उनका इस्तीफा मांगा। प्रदर्शनकारियों ने दोनों नेताओं पर महिलाओं के अपमान और महिला विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में शामिल सपा नेता समयून खान और ममता चौधरी के साथ प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और नेताओं के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का–मुक्की और तीखी नोकझोंक हुई। समयून खान ने कहा कि मंत्री संजय निषाद द्वारा दिया गया बयान महिलाओं का सीधा

अपमान है। जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक महिला का नहीं बल्कि पूरे समाज का अपमान है। ऐसे लोग अगर मंत्री पद पर होंगे तो महिलाओं को न्याय और सम्मान कैसे मिलेगा। संजय निषाद का बयान सभ्य समाज पर धब्बा है। जिस कृत्य कि निंदा करना चाहिए था उसको समर्थन देकर महिला अपराध और महिलाओं के प्रति सामजिक नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिला सम्मान के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया । उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत से समाज में महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता उजागर होती है। महिलाओं के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक संजय निषाद और नीतीश कुमार इस्तिका देकर माफी नहीं मांगते, तब तक विरोध जारी रहेगा। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करने वाली सरकार के लोगों के चेहरे से नकाब हट गया।

एलडीए जनता अदालत में पेट पर शिकायत चिपकाकर अधिकारी से मिला फरियादी

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के कर्मियों की कार्यशैली से आजिज आकर अधिकारियों से यूनीक तरीके से शिकायत की। वह अपनी शिकायत पेट पर चिपकाकर एलडीए ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने बताया कि घर के पास एक टावर लगा है। उसे हटवाने के लिए 8 महीने से दौड़ रहा हूं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यह देखने को मिला गुरुवार को एलडीए में आयोजित जनता अदालत में। इस दौरान दूसरे फरियादी भी पहुंचे जिन्होंने अपनी शिकायतें दीं। साथ ही नगर निगम के एक पार्षद भी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि उनके वार्ड में भूमाफिया सरकारी जमीन पर होटल बनवा रहा है। उसे अधिकारी नहीं रोक रहे। गोमतीनगर से एक बुजुर्ग अपने घर के पास लगे टावर को हटवाने की शिकायत लेकर पहुंचे। सुरेश चंद्र ने बताया मेरे घर के पास में एक टावर लगा है। उसे हटाने की शिकायत वह 8 महीने से कर रहा हूं। अफसरों ने टावर हटाने के निर्देश भी दिए थे पर 8 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक वह नहीं हटा है। टावर मालिक से प्राधिकरण के अफसर मिल गए हैं इसीलिए टावर नहीं हट रहा। आशियाना रेजीडेंसी एसोसिएशन अध्यक्ष आरके पांडेय ने कहा आशियाना योजना बनाते समय अंसल ने सभी सेक्टरों में पार्क और कम्युनिटी सेंटर बनाने का वादा किया था। बाद में उसने जमीनों को बेच दिया। आवंटियों के दबाव के बाद अंसल ने आशियाना के सेक्टर–के में डेढ़ एकड़ जगह दी थी। उसके एक हिस्से में सभी आवंटियों ने पैसे से एक मंदिर बनवाया। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मंदिर में अपना पुजारी बैठा दिया है। उस जमीन पर लखनऊ विकास प्राधिकरण अब कम्युनिटी सेंटर बनाने जा रहा है, जबकि पूरी योजना में सिर्फ एक पार्क है। इसके साथ ही एसोसिएशन ने शिकायत की है कि पार्क पर किसी तरह का कोई निर्माण नहीं करवाया जाए। इब्राहिमपुर वार्ड के पार्षद बृजमोहन शर्मा ने बताया कि उनके वार्ड में हरिहर नगर स्थित सरकारी जमीन पर माफिया कब्जा करके होटल बना रहे हैं। 2016 में महेश वर्मा नाम के भूमाफिया पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इसके बाद से उसने होटल के निर्माण का काम बंद कर दिया था। लेकिन 10 दिनों से आरोपी बिल्डर ने फिर से होटल निर्माण का काम शुरू कर दिया है। इसको लेकर के लखनऊ विकास प्राधिकरण के जेई और नगर निगम के तहसीलदार से कई बार शिकायत की पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इसकी शिकायत लेकर एलडीए वीसी से मिलने आए।

नीतीश-संजय के खिलाफ होर्डिंग वार, सपा नेता बोले महिला सम्मान का नारा खोखला

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ में सपा कार्यालय के पास लगी होर्डिंग। समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ होर्डिंग वार। यह होर्डिंग सपा कार्यालय और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद के आवास के बीच लगाई गई, इस के माध्यम से दोनों नेताओं पर तीखे शब्दों में हमला बोला गया है। पोस्टर के माध्यम से सपा नेता ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए लिखा है नियुक्ति पत्र मांगती बच्चियां, हिजाब हटाया जा रहा। के जरिए सरकार की नीतियों और सामाजिक मुद्दों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। पोस्टर में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि युवतियों और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मुद्दों पर सरकार संवेदनशील नहीं है। होर्डिंग पर लिखा संदेश नियुक्ति पत्र माँगती बच्चियाँ, हिजाब हटाया जा रहा, सत्ता के घमंड में मंत्री, मर्यादा भूले जा रहे। छुआ ही तो क्या कहकर, जुर्म को हल्का बताते हैं, नारी सम्मान पर हँसी और खुद को नेता बताते हैं। अखिलेश यादव ढाल बनकर, हर नारी के सम्मान के साथ है। होर्डिंग में इन्हीं शब्दों के साथ संजय निषाद और नीतीश कुमार पर हमला किया गया है तो वहीं अखिलेश यादव को नारी सम्मान का मसीहा बताया। सपा नेता मोहम्मद इखलाक ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा सरकार में मंत्री संजय निषाद दोनों ही महिला विरोधी हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी भी यह बताती है कि वह इन दोनों नेताओं के कृत्य और बयान का समर्थन कर रही है। सरकार के द्वारा महिला सम्मान का दिया जाने वाला नारा पूरी तरह झूठ और खोखला है हम लोग इसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं और यह विरोध आगे भी जारी रहेगा।

सीएम ने रिमोट से भातखंडे विश्वविद्यालय का 15 रुपए का डाक टिकट दिखाया

संवाददाता

लखनऊ। अवस्थीजी कहां हैं? आप अकेले आई हैं? मुझे उन्होंने ही सुबह समारोह की सूचना दी और खुद गायब हो गए, वह भी अच्छे कलाकार हैं। सीएम योगी ने लखनऊ में लोक गायिका मालिनी अवस्थी से हुए इस संवाद के बारे में बताया तो पूरा सभागार ठहाकों से गूंज उठा। मौका था भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष समारोह का। सीएम योगी, समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। समारोह में कथक नृत्यांगना पूर्णिमा पांडेय, मालिनी अवस्थी सहित चार पूर्व छात्र–छात्राओं को सम्मानित किया गया।

शहीदपथ पर धू-धूकर जलने लगी कार,दो सवार उतरकर भागे

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी में शहीदपथ पर एक कार धू–धूकर जलने लगी। उसमें दो लोग सवार थे। जैसे ही बोनट से धुआं निकलने लगा वे दोनों तुरंत उतरकर भागे। दमकल को इसकी सूचना दी लेकिन जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंची तब तक कार का केवल फ्रेम बचा था। 20 मिनट में पहुंचे दमकलकर्मियों ने आग बुझाई। घटना गुरुवार दोपहर हुई। तेलीबाग के खुर्रम आसिफ अपने ड्राइवर कलीम के साथ साउथ सिटी जा रहे थे। वह जैसे ही शहीदपथ के नीचे सर्विस लेन पर सेक्टर–जे के पास पहुंचे कार के बोनट से धुआं निकलता दिखा। कार रोककर दोनों लोग जल्दी से उतरे और विस्फोट होने के डर से दूर भाग गए। कार मालिक खुर्रम का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है और तेलीबाग में एक पेट्रोल पंप है।

कोडीन–युक्त कफ सिरप की अवैध आपूर्ति में संलिप्त लोगों को बचा रही भाजपा : अखिलेश यादव

संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर करोड़ों रुपये के कोडीन–युक्त कफ सिरप की अवैध आपूर्ति में संलिप्त लोगों को बचाने का आरोप लगाया। यादव ने सपा विधायकों की बैठक के बाद यहां पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा के आने वाले सत्र में उठाए जाने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें कथित कोडीन और कफ सिरप रैकेट एक बड़ी चिंता का विषय था। उन्होंने आरोप लगाया, "कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर चिंता सिर्फ उत्तर प्रदेश के आम लोगों तक सीमित नहीं है। यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। यह रैकेट एक प्रधान सांसद (वाराणसी) के इलाके से शुरू हुआ और इसके तार न सिर्फ पूरे देश बल्कि विदेशों तक फैले हुए हैं। यादव ने दावा किया कि जो शुरू में कुछ करोड़ रुपये का घोटाला लग रहा था।

दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, महिलाओं से की अभद्रता

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। महिलाओं से छेड़छाड़ करने के साथ ही जानलेवा हमला किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पीड़ित ने इस मामले में थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। गोमती नगर विस्तार निवासी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि उनके मोहल्ले में विजय द्विवेदी, अंकुर द्विवेदी, बृजेश द्विवेदी और विक्की द्विवेदी घर बनवा रहें है। गुरुवार सुबह निर्माण सामग्री से लदा एक ट्रक संकरी सड़क से गुजर रहा था। इस दौरान सत्येंद्र की वृद्ध मां ने ट्रक चालक से सड़क संकरी होने के कारण सावधानी से ट्रक निकालने को कहा, जिस पर चालक से कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसके बाद मकान बनवाने वाले चारों

लोग मौके पर पहुंचे और गाली–गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। दबंगों ने पीड़ित के घर में घुसकर सत्येंद्र, उनकी मां, बहन और भाई के साथ मारपीट की। इस दौरान महिलाओं के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ भी की गई। बीच–बचाव करने आए एक युवक पर ईंट से हमला कर उसका सिर फोड़ दिया गया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

यूपी विधानमंडल: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सदन में चर्चा करा सकती है सरकार

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से शुरु हो रहे राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले गुरुवार को विधानभवन में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने की। सूत्रों के अनुसार सरकार वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सदन में विशेष चर्चा कराने पर विचार कर रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, बसपा नेता उमा शंकर सिंह, कांग्रेस नेता

आराधना मिश्रा सहित विभिन्न दलों के नेता मौजूद रहे। इससे पहले शीतकालीन सत्र की रूपरेखा तय करने के लिए कार्यमंत्रणा समिति की बैठक भी बुलाई गई। सूत्रों के अनुसार सरकार वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सदन में विशेष चर्चा कराने पर विचार कर रही है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिया जाएगा। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा। सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। सर्वदलीय बैठक में शामिल होने जाते समय समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मल्होत्रा ने कहा कि सरकार जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती है, इसी वजह से शीतकालीन सत्र को इतना छोटा रखा गया है। उन्होंने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता से जुड़े सवालों पर विस्तार से चर्चा जरूरी है।

काकोरी में भगवान पार्श्वनाथ की भव्य रथयात्रा, पंचकल्याणक महोत्सव की घोषणा

संवाददाता

लखनऊ। काकोरी स्थित भगवान पारसनाथ धाम में भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक दिवस पर वार्षिक रथयात्रा का भव्य आयोजन किया गया। इस उत्सव में संपूर्ण अवध क्षेत्र से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ भाग लिया।

जून 2026 में होगा ऐतिहासिक पंचकल्याणक मुख्य संयोजक ब्रिजेश जैन बंटी ने इस अवसर पर एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि आगामी 24 से 29 जून 2026 तक चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में 21 फीट ऊँची आदिनाथ भगवान की प्रतिमा का भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित होगा। नवगठित समिति ने भगवान के चरणों में श्रीफल अर्पित कर महोत्सव की सफलता का आशीर्वाद लिया पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के अध्यक्ष, संजीव जैन, कार्याध्यक्ष, जागेश जैन, महामंत्री, संदीप जैन, कोषाध्यक्ष, रितेश जैन, मुख्य संयोजक, ब्रिजेश जैन बंटी उपाध्यक्ष सुरेंद्र जैन, राकेश जैन सह–मंत्री, विशाल जैन (वास्तुकार) सह–कोषाध्यक्ष, विशाल जैन संयोजक, भारतेंदु जैन (मंदिर), जय कुमार जैन (अवध क्षेत्र) महोत्सव की तैयारियां पूरे अवध क्षेत्र में उत्साह के साथ शुरू कर दी गई हैं।

बाबा के बताए मार्ग पर चलकर ही बनेगा विकसित छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

लालपुर में महाविद्यालय की घोषणा सहित विकास कार्यों की सौगात
सरकार प्रत्येक पात्र किसान से धान खरीदी के लिए पूर्णतः संकल्पित
मंदिर एवं जैतखाम में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृध्दि की कामना
लालपुर धाम में गुरु घासीदास जयंती एवं तीन दिवसीय मेले में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय

बीएनई

रायपुर। बाबा गुरु घासीदास द्वारा बताए गए सत्य, समानता और

मानवता के मार्ग पर चलकर ही छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महापुरुषों के आदर्शों और सपनों के अनुरूप समतामूलक, न्यायपूर्ण और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुंगेली जिले के लालपुर में आयोजित गुरु घासीदास जयंती एवं तीन दिवसीय मेला कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर लालपुर में नवीन महाविद्यालय की स्थापना, मेला एवं कार्यक्रम आयोजन हेतु दी जाने वाली राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने, कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश द्वार निर्माण के लिए 25 लाख रुपये तथा मुंगेली सतनाम भवन के जीर्णोद्धार हेतु 25 लाख रुपये की स्वीकृति की घोषणा की। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री साय ने बाबा गुरु घासीदास मंदिर एवं जैतखाम में विधिवत पूजा–अर्चना कर प्रदेश की सुख–समृद्धि, खुशहाली और जनकल्याण के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अधिकांश गारंटियों को पूरा किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्येक पात्र किसान से धान खरीदी के लिए पूर्णतः संकल्पित है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बीते दो वर्षों में धान के रकबे और किसानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है। पीएसी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नई औद्योगिक नीति लागू की गई है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग का बेटा–बेटी उद्यमी बन सके। उन्होंने सभी के सहयोग से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का आह्वान किया। इस अवसर पर सतनाम आचार संहिता एवं जागरूकता कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अनुसूचित जाति प्राधिकरण को सशक्त करते हुए इसके बजट को 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये किया गया है। कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में सर्व समाज का समावेशी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित समाज के पांच प्रतिभावान बेटा–बेटियों को पायलट प्रशिक्षण हेतु 15–15 लाख रुपये की सहायता देने का निर्णय सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा, पूर्व विधायक सनम जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडेय, उपाध्यक्ष शांति देवचरण भास्कर, जनपद अध्यक्ष लोरमी वर्षा विक्रम सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष सुजीत वर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में सतनामी समाज के अनुयायी उपस्थित थे।

बांदा में वृहद रोजगार मेले का हुआ आयोजन, सैकड़ो बेरोजगार अभ्यर्थियों का हुआ चयन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के मिशन रोजगार के तहत क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय ने किया रोजगार मेले का आयोजन
प्रदेश और देश की कई कंपनियों मेले में लिया प्रतिभाग
सैकड़ो पदों के लिए कंपनियों ने लिया अभ्यर्थियों का साक्षात्कार

बीएनई

बांदा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के मिशन रोजगार के तहत गुरुवार को बांदा में सेवा नियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज मटौंध में एक दिवसीय बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिसमें लगभग 350 बेरोजगार अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया और यहां पर आई कई कंपनियों ने उनका साक्षात्कार लिया। जिसमें कुल 193 बेरोजगार अभ्यर्थियों का चयन किया गया। और सरकार के मिशन रोजगार के तहत इन सभी अभ्यर्थियों को अलग–अलग कंपनियों में नौकरी मिली।

5 कंपनियों ने 350 अभ्यर्थियों में 193 अभ्यर्थियों का किया चयन

उक्त रोजगार मेले में 5 कंपनियों ने अभ्यर्थियों का चयन किया। जिसमें आमधन–ई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 12 अभ्यर्थियों का चयन किया, वहीं रिलायंस निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 37 अभ्यर्थियों का, एजुवेंटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 16, सारा सिक्योरिटी सॉल्यूशन ने 128 व जीवितम कंपनी ने 23 अभ्यर्थियों का चयन किया। और कुल 193 बेरोजगार अभ्यर्थियों को इस रोजगार मेले में नौकरी मिली। बृहद रोजगार मेले का उद्घाटन जिला विद्यालय निरीक्षक बांदा दिनेश कुमार द्वारा किया गया एवं इस अवसर पर सहायक निदेशक सेवायोजन अहमद अंसारी, जिला सेवायोजन अधिकारी मोहित जायसवाल तथा राजकीय इंटर कॉलेज मटौंध की प्रधानाचार्य प्रियंका सिंह उपस्थित रहीं। इन लोगों के द्वारा चयनित हुए अभ्यर्थियों को बधाई दी गई और कहा कि सभी अभ्यर्थी अब अपने दायित्वों का सही से निर्वहन करें। वही इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के मिशन रोजगार के तहत इस मेले का आयोजन कराया गया था। जिसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरियां मिल सके।

संक्षिप्त

टेनिस जगत में बड़ा बदलाव, अल्कराज-फरेरो की सफल जोड़ी बिछड़ी, खत्म हुई सात साल की साझेदारी

एजेंसी

नई दिल्ली। विश्व के शीर्ष रैंकिंग वाले टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने अपने लंबे समय से कोच रहे जुआन कार्लोस फरेरो के साथ सात साल की सफल साझेदारी समाप्त करने का फैसला किया है। फरेरो वही कोच हैं जिन्होंने अल्कराज को पुरुष टेनिस के शिखर तक पहुंचाया। 15 साल की उम्र से फरेरो ने दी अल्काराज को कोचिंग अल्कराज ने बुधवार को सोशल मीडिया पर इस फैसले की घोषणा की। वहीं फरेरो ने अलग बयान में अपने शिष्य का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे इस साझेदारी को जारी रखना चाहते थे। फरेरो ने अल्कराज को 15 साल की उम्र से कोचिंग दी, जिसके दम पर स्पेनिश स्टार ने कुल छह ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। इनमें दो फ्रेंच ओपन, दो विंबलडन और दो यूएस ओपन शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने 24 एटीपी टूर खिताब अपने नाम किए, जिनमें आठ मास्टर्स 1000 ट्रॉफियां शामिल हैं। 22 वर्षीय अल्कराज ने लिखा, सात साल से ज्यादा समय साथ बिताने के बाद, जुआनकी और मैंने कोच और खिलाड़ी के रूप में अपनी यात्रा को यहीं समाप्त करने का फैसला किया है। मेरे बचपन के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए धन्यवाद। जब हमने यह सफर शुरू किया था, तब मैं बस एक बच्चा था। आपने कोर्ट के अंदर और बाहर, हर कदम पर मेरा साथ दिया। मैंने इस यात्रा के हर पल का भरपूर आनंद लिया। अलविदा कहना कभी आसान नहीं होता फरेरो के साथ ही अल्कराज 2022 में 19 साल की उम्र में यूएस ओपन जीतकर एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। फरेरो ने कहा, आज का दिन मुश्किल है। ऐसे मौकों पर सही शब्द ढूंढना आसान नहीं होता। अलविदा कहना कभी आसान नहीं होता, खासकर तब जब इतने अनुभव साथ साझा किए हों। हमने कड़ी मेहनत की, साथ बढ़े और अविस्मरणीय पल जिए।

सात फीसदी की रफ्तार से बढ़ेगी जीडीपी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर बोलीं IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री

एजेंसी

नई दिल्ली। वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में मजबूत रफ्तार बनाए रख सकती है। अनुमान है कि देश की जीडीपी करीब सात फीसदी की दर से बढ़ेगी। यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

के 6.6 फीसदी के अनुमान से बेहतर प्रदर्शन है और अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत देता है। आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारत की वृद्धि दर पर आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जुलाई–सितंबर तिमाही के आंकड़े आने से पहले किया गया था। इस तिमाही में भारत की विकास दर 8.2 फीसदी रही। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.8 फीसदी से बढ़ाकर 7.3 फीसदी कर दिया है। विकसित भारत का रास्ता गीता गोपीनाथ के मुताबिक, यदि भारत अगले करीब 20 वर्षों तक लगभग आठ फीसदी की विकास दर बनाए रखता है, तो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के काफी करीब पहुंच सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इतनी लंबी अवधि तक ऊंची विकास दर बनाए रखना आसान नहीं है। इसके लिए निरंतर आर्थिक सुधार, निवेश बढ़ाने और उत्पादकता सुधारने की जरूरत होगी। अमेरिका व्यापार संकट से बेहतर स्थिति गोपीनाथ ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार संकट से पहले की गई भविष्यवाणियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। टैरिफ दरें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन अमेरिकी नजरिये से देखा जाए तो चरम टैरिफ का दौर निकल चुका है। 2026 में अमेरिका में मध्यावधि चुनाव हैं और चुनाव से पहले ज्यादा अनिश्चितता की संभावना कम मानी जा रही है। टैरिफ, महंगाई और ऊर्जा नीति उन्होंने कहा कि टैरिफ बढ़ने से महंगाई पर दबाव बढ़ा है और जीवनयापन की लागत में इजाफा हुआ है। यह एक नई चुनौती बनकर सामने आई है। गोपीनाथ का मानना है कि भारत और अमेरिका को मिलकर आपसी समाधान निकालना चाहिए। तेल की कीमतें 60 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहने से भारत के पास रूस के अलावा अन्य देशों के साथ ऊर्जा साझेदारी बढ़ाने का अवसर भी है। आर्थिक संभावनाओं के बावजूद गोपीनाथ ने नियामकीय जटिलताओं को बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करना अब भी आसान नहीं है। यदि नियमों को सरल बनाया जाए और सुधारों की रफ्तार तेज हो, तो भारत न केवल ऊंची विकास दर बनाए रख सकता है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है।

एनपीएस में बड़ा बदलाव, निवेशकों को मिली बड़ी राहत; अब 80 फीसदी तक पैसा निकालने की छूट

एजेंसी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस से जुड़े गैर–सरकारी सदस्यों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब एनपीएस खाताधारक अपनी जमा निधि का 80 प्रतिशत तक पैसा

एकमुश्त निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा 60 प्रतिशत थी। इस फैसले से करोड़ों निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और स्व–रोजगार से जुड़े निवेशकों को सेवानिवृत्ति के समय अधिक नकदी उपलब्ध होगी। यह बदलाव पेंशन प्रणाली को अधिक लचीला और उपयोगी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए ने एनपीएस से निकासी के नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत निकासी की अधिकतम आयु को 70 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब खाताधारक लंबे समय तक अपने एनपीएस खाते को जारी रख सकेंगे और जरूरत के अनुसार पैसा निकाल पाएंगे। पहले शेष 40 प्रतिशत राशि से एन्युटी खरीदना अनिवार्य था, जिससे मासिक पेंशन मिलती थी, लेकिन अब यह बाध्यता कम हो गई है। खाते को गिरवी रख कर्ज की सुविधा नए नियमों के तहत एनपीएस खातों को गिरवी रखकर तय सीमा के भीतर वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने की भी अनुमति दी गई है। इससे जरूरत के समय खाताधारकों को कर्ज लेने में आसानी होगी और उन्हें अपनी पेंशन बचत तोड़ने की मजबूरी नहीं रहेगी। यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है, जिन्हें रिटायरमेंट से पहले या बाद में बड़ी राशि की जरूरत पड़ती है। आठ लाख से कम राशि वालों को पूरी छूट पीएफआरडीए के अनुसार यदि किसी एनपीएस खाताधारक की कुल पेंशन निधि 8 लाख रुपये से कम है, तो वह पूरी राशि एकमुश्त निकाल सकता है। इसके अलावा ग्राहक को यह विकल्प भी मिलेगा कि वह नियमित अंतराल पर एकमुश्त निकासी या यूनिट रिडेम्पशन के जरिए भुगतान ले सके।

शेयर बाजार लाल निशान पर खुला; सेंसेक्स 215 अंक टूटा, निफ्टी में भी गिरावट

एजेंसी

नई दिल्ली। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुझान के चलते गुरुवार को शुरुआती कारोबार में इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 214.87 अंक गिरकर 84,344.78 पर आ गया। वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 56.1 अंक गिरकर 25,762.45 पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में गुरुवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सीमित दायरे में कारोबार करता रहा, क्योंकि विदेशी निधियों के नए प्रवाह से मिलने वाला समर्थन व्यापार समझौते की अनिश्चितता और जोखिम से बचने की भावना से बेअसर हो गया। सेंसेक्स में सूचीबद्ध कंपनियों में से सन फार्मा, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मारुति सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाली कंपनियों में शामिल थीं। हालांकि, एचसीएल टेक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा और आईटीसी लाभ कमाने वाली कंपनियों में शामिल थीं। एशियाई बाजारों में रहा मिला–जुला हाल एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक नीचे दर्ज किए गए, जबकि शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक सकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहा था। अमेरिकी बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुए। अमेरिका में रात भर हुई भारी बिकवाली के बाद वैश्विक बाजार आज के सत्र में सतर्कता के साथ प्रवेश कर रहे हैं। एसएंडपी 500, नैस्डैक और डाउ ने अपनी गिरावट जारी रखी क्योंकि निवेशकों ने उच्च मूल्यांकन वाली प्रौद्योगिकी और एआई शेयरों में मुनाफा कमाया। अमेरिकी आर्थिक आंकड़े जारी होने से पहले

निवेशक सर्तक ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेल्थ टेक फर्म एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा कि अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के आंकड़ों के जारी होने से पहले निवेशकों का नजरिया भी सतर्क बना हुआ है, क्योंकि मौद्रिक नीति के भविष्य के प्रक्षेप पथ पर बाजार में विभाजित विचार हैं, जो प्रतिभागियों को रक्षात्मक रुख अपनाने और आक्रामक स्थिति से बचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि लगातार कई सत्रों की बिकवाली के बाद वॉल स्ट्रीट पर छाए सुस्त माहौल को दर्शाते हुए एशियाई बाजारों की शुरुआत कमजोर रही। विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार पर भरोसा लौटा चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड की तकनीकी और डेरिवेटिव विश्लेषक अमृता शिंदे ने कहा कि संस्थागत मोर्चे पर, एफआईआई पिछले 14 सत्रों तक विक्रेता रहने के बाद 17 दिसंबर को शुद्ध खरीदार बन गए और उन्होंने 1,171 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि डीआईआई भी 768 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी के साथ सहायक बने रहे। शिंदे ने आगे कहा कि बाजार के प्रतिभागी सत्र के दौरान वैश्विक इक्विटी रुझानों, कच्चे तेल की कीमतों में उतार–चढ़ाव और संस्थागत निधि प्रवाह पर नजर रखेंगे ताकि उन्हें बाजार में तेजी की दिशा का पता चल सके।

प्रभास की हीरोइन के साथ भीड़ ने की बदतमीजी, कार में बैठते ही ली राहत की सांस; वीडियो देख भड़के फैंस

एजेंसी

हैदराबाद में प्रभास की आने वाली फिल्म द राजा साब के प्रमोशनल इवेंट के दौरान ऐसा वाकया सामने आया, जिसने एक बार फिर से सेलेब्रिटीज की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सॉन्ग लॉन्च जैसे भव्य कार्यक्रम के बाद जब

अभिनेत्री निधि अग्रवाल वेन्यू से बाहर निकल रही थीं, तभी हालात अचानक बेकाबू हो गए। भारी संख्या में मौजूद लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा–तफरी का माहौल बन गया। निधि अग्रवाल को भीड़ ने घेरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोज के मुताबिक, इवेंट खत्म होते ही लोग निधि अग्रवाल के बेहद करीब आ गए। कोई सेल्फी लेना चाहता था तो कोई वीडियो बनाने में जुटा था। इसी बीच भीड़ का दबाव इतना बढ़ गया कि अभिनेत्री को अपनी कार तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। चारों तरफ से घिरी निधि के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। आखिरकार सुरक्षा कर्मियों ने घेरा बनाकर उन्हें किसी तरह कार तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह अभिनेत्री की गाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रही थी और लोग उनके बेहद करीब पहुंच गए थे। जैसे ही निधि कार में बैठीं, उनके चेहरे पर राहत के साथ–साथ असहजता भी साफ दिखाई दी। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। कई लोगों ने इसे फैन कल्चर की हद पार होना बताया है। यूजर्स का कहना है कि स्टार्स की लोकप्रियता का मतलब यह नहीं कि उनकी निजी सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया जाए। कुछ लोगों ने आयोजकों को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इतने बड़े सितारे के इवेंट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे। वहीं, कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि प्रशंसा और बदतमीजी के बीच की लाइन अब धुंधली होती जा रही है। मुन्ना माइकल से की थी शुरुआत निधि अग्रवाल की बात करें तो उन्होंने हिंदी सिनेमा में फिल्म मुन्ना माइकल से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। आईस्मार्ट शंकर, ईश्वरन और हरि हर वीरा मल्लु जैसी फिल्मों में उनके काम को खासा सराहा गया। अब वह प्रभास के साथ द राजा साब में नजर आने वाली हैं, जिसे लेकर फैंस में पहले से ही जबरदस्त उत्साह है। मारुति के निर्देशन में बन रही श्द राजा साबश एक पैन–इंडिया फिल्म है, जिसमें प्रभास के साथ संजय दत्त, मालविका मोहनन और रिद्धि कुमार जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म की रिलीज को लेकर चर्चा जोरों पर है और यह अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743